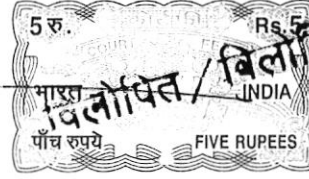
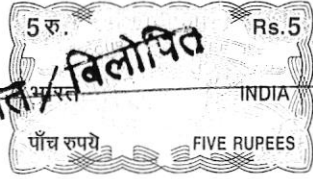
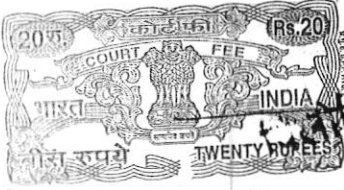


29

न्यायालय श्री मा. ज. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ग्वालियर, कैम्प कोर्ट, रावा मण्डल



Rs. 30/-

R 5046-II/17

तख न कुमार तनय श्री जगदीश प्रताप गौतम, उम्र 72 साल, पेशा खेती

निवासी ग्राम भित्वा, तहसील हनुमानगढ़ जिला रावा मण्डल

— निगरानी करी

बनाम

अधीन श्री सुशील कुमार
शुक्ला द्वारा यत्कृत 2-2-17

1:- सुरेश कुमार तनय श्री शीतला प्रताप पाण्डेय सा. बिबिध्या रावा, तहसील हनुमानगढ़

2:- रीपुदमन पाण्डेय तनय स्व. सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय

2:- देवा विमलेश पाण्डेय पत्नी स्व. सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय

तलवा ताताब के पास चिरहुला, तहसील हनुमानगढ़ जिला रावा

3:- देवेन्द्र कुमार तनय श्री शीतला प्रताप पाण्डेय सा. बिबिध्या रावा

तहसील हनुमानगढ़ जिला रावा मण्डल

— गैर निगरानी करी गण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय ^{मानु} अपर

आयुक्त महोदय रावा सम्भाग रावा तहसील हनुमानगढ़

रावा प्र. 0, 655/निगरानी/06-07

आदेश दि. 25-01-2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मण्डल भू रा. 0 सं. 0

1959 ई. 0

मानव्यर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यही अधीन न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:- यह कि गैर निगरानी करी ने विचारण न्यायालय के आदेश दि. 14-11-2001 के विरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय रावा के समक्ष दि. 19-6-2003 को फौजदारी जिले में यह अभिप्रेषण किया कि

विचारण न्यायालय के आदेश दि. 14-11-2001 को जानकारी गैर निगरानी करी

श्रीराम कुमार

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/5046/दो/17 जिला-रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/5/18	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शुक्ला उपस्थित होकर उनके द्वारा, यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा प्रकरण क्रमांक 655/निगरानी/06-07 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2017 के विरुद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 14/11/2001 के विरुद्ध दिनांक 19/06/2003 को अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की, उनके द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया है कि विचारण न्यायालय में अनावेदक पक्षकार नहीं था इसलिए उसे उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। इसलिए उनके द्वारा धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर विलंब को क्षमा किया है इसी से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की थी। उनके द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर यह पाया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब</p>	

तहसीलदार वृत्त वनकुईया के द्वारा दिनांक 14/11/2001 को उपरोक्त वर्णित आराजियों का अपीलार्थी को भूमि घोषित किया गया है। आराजी न. 186 व आराजी न. 162 गैर निगरानीकर्ता के आबादी व निस्तार की भूमि थी जिन्हें प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक के अपील को समय सीमा में मान्य कर प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का पालन करते हुए आदेश पारित किया गया है। जिसमें अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के कारण हस्तक्षेप योग्य नहीं माना। उनका आदेश स्थिर रखा है। अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखने योग्य है।

3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 655/निगरानी/06-07 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य